(d) if not, whether such equipment will be despatched immediately to facilitate completion of this work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The equipment and cable etc. have been ordered. The scheme is likely to be commissioned by March' 99 subject to timely availability of equipment and cable.

### राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी संघ की बैठक

526. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 जुलाई, 1998 को राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी संघ (भारत) वर्ग "ग" के पदाधिकारियों की तत्कालीन संचार मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ बैठक हुई थी जिसमें दूरसंचार सचिव और सदस्य (सेवाएं) ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में की गई मांगों पर सहमति के कारण सदस्य (सेवाएं) द्वारा 13 अगस्त, 1998 को संघ के पदाधिकारियों के साथ पुनः एक विभागीय बैठक बुलाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगे क्या थी;

(घ) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन-किन मांगों पर सहमति हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक मांग पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ):** (क) जी, नहीं।

(ख) संघ की मांगों पर विचार करने के लिए संघ के सदस्यों की 13.8.98 की सदस्य (सेवाएं) के साथ अनौपचारिक बैठक हुई।

(ग) से (ङ) मुख्य मांगे मुख्यतः फोन मैकेनिकों/तकनीशियनों/टी०टी०ए० इत्यादि के लिए बेहतर सेवा अवसरों (पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों से उच्चतर वेतनमानों सहित) से संबद्ध है। एसोसिएशन के सदस्य यह भी चाहते हैं कि फोन मैकेनिक की टी०टी०ए० के संवर्ग पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि को कम करके 2-3 वर्ष तक कर दिया जाए। बैठक में उनकी मांगों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। ऐसी मांगों के लिए जिनमें 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन निहित था, संघ के सदस्यों को यह मामला, स्टाफ पक्ष के सचिव के जरिए विभागीय विसंगति समिति में उठाए जाने की सलाह दी गई थी।

### New Project to Establish Telephone Exchanges in Manipur

527. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a new project to establish telephone exchanges in Manipur;

(b) if so, whether the locations, etc. have since been finalised; and

(c) by when the proposed project likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Seven new telephone exchanges are proposed to be set up by March, 1999.

### नई केबल लाइनें

528. **श्री डी० पी० यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में बिछाई गई नई केबल लाइनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में कुल कितने नए केन्द्रों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा गया है;

(ग) क्या विभाग लम्बी दूरी के कॉलों पर प्रभार घटाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ):** (क) चालू वर्ष के दौरान 30.9.98 तक 120 एल० सी० के० एम० (लाख कंडक्टर किलोमीटर) केबिल बिछा दी गई है।

(ख) 1.4.98 से 31.10.98 तक कुल 610 नए स्थानों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ग) और (घ) टी० आर० ए० आई० अधिनियम, 1997 के अधीन गठित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को दूरसंचार सेवाओं की दरें निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ पर एक परामर्श दस्तावेज निकाला है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लम्बी दूरी की कॉल प्रभारों में कमी करने का भी प्रस्ताव है। टैरिफ ढाँचों को अंतिम रूप देने से पूर्व टी० आर० ए० आई० ने सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता संगठनों तथा आम जनता से परामर्श लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि इस बारे में उनके विचार सुनिश्चित किए जा सकें। टी० आर० ए० आई० द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले टैरिफ पर निर्णय लेने की समय-सीमा परामर्श प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

**Modernisation of Post Offices**

529. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to modernise and improve certain post offices in the capital;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the idea behind improving the post offices of the capital only?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) to (c) Yes, Sir. Modernisation of Post Offices has been taken up as a part of the plan activities of the Department since the 8th Five Year Plan to enhance working ambience and ergonomics of the post offices all over the country for greater customer satisfaction and to increase productivity of the employees. Accordingly, for the current financial year, 8 post offices of Delhi Circle have been identified for modernisation and 52 post offices in other parts of the country.

**Licences to Private Internet Companies**

530. SHRI S.M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have recently decided to give licences to private internet companies, if so, the terms and conditions thereof;

(b) the names of treating private companies presently operating in the company and rules governing their operation;

(c) whether it is a fact that the private companies are not satisfied with VSNL MTNL functioning and have in fact requested for satellite use directly, if so, the reaction of Government on their request; and

(d) what would be the implications of direct use of satellite by such companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir. A synopsis of the terms and conditions is given in the Statement-I (*See* below).

(b) The new Internet Policy has been announced on 6th November, 1998. Till date 19 licences have been issued to private companies. A list of these companies is given in Statement-II (*See* below). M/s. Satyam Infoway who were given a licence on 12th November, 98 have launched their services at Hyderabad on 22.11.98. Many other companies plan to do so in the near future. The synopsis of the terms and conditions of their operations are Statement-III (*See* below).

(c) and (d) No, Sir. No request has been received from any of the ISPs for direct use of satellite circuits. However, any proposal received from them will be examined in the light of Satcom Policy and also of interference with other agencies using the same frequency spectrum for communication, broadcast etc.

**Statement-I**

**Synopsis of Terms and Conditions—ISP**

(a) Any Indian company with a maximum foreign equity of 49% is eligible.